

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] No. 101 नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5-मार्च 11, 2011 (फाल्गुन 14, 1932)

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5-MARCH 11, 2011 (PHALGUNA 14, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकार्यो द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सिम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002, दिनांक 31 जनवरी 2011

सं. आर-12/19/1/2001-हित-2--कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 14.12.1980 के संकल्प जिसमें महानिदेशक को ऐसी शिक्तयों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया है, के साथ पठित क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 75 के अंतर्गत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने का.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 54 तथा 54-क के प्रयोजनार्थ तथा निगम के दिनांक 28.02.1976 के संकल्प (यथा संशोधित) के पैरा 4 के अंतर्गत मामलों की जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित चिकित्सा बोर्ड का गठन किया है:--

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल, गुड़गाँव (हरियाणा)

अध्यक्ष

2. विशेषज्ञ (हड्डी) क.रा.बी. अस्पताल, गुड़गाँव

सदस्य

3. विशेषज्ञ (शल्य चिकित्सा) क.रा.बी. अस्पताल, गुड़गाँव

सदस्य

बोर्ड के अध्यक्ष को, जांच किए जाने वाले बीमाकृत व्यक्ति की निशक्तता को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक होने पर, उपरिलिखित विशेषज्ञ सदस्य के स्थान पर अथवा उसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों अथवा अपने क्षेत्राधीन किसी अन्य सार्वजनिक/निजी चिकित्सा संस्थान से किसी अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित करने का प्राधिकार है।

अधिकार क्षेत्र : बोर्ड को संपूर्ण उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुड़गाँव के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार होगा।

बी. के. साहू बीमा आयुक्त

सं. आर-12/9/1/2007-हित-2--कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 14.12.1980 के संकल्प जिसमें महानिदेशक को ऐसी शिक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया है, के साथ पठित क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 75 के अंतर्गत शिक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 54 तथा 54-क के प्रयोजनार्थ तथा निगम के दिनांक 28.02.1976 के संकल्प (यथा संशोधित) के पैरा 4 के अंतर्गत मामलों की जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित चिकित्सा बोर्ड का गठन किया है:--

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. मॉडल अस्पताल, बापूनगर (गुजरात)

अध्यक्ष

2. विशेषज्ञ (हड्डी) क.रा.बी. मॉडल अस्पताल, बापूनगर (गुजरात)

सदस्य

3. विशेषज्ञ (शल्य चिकित्सा) क.रा.बी. मॉडल अस्पताल, बापूनगर (गुजरात)

सदस्य

बोर्ड के अध्यक्ष को, जांच किए जाने वाले बीमाकृत व्यक्ति की निशक्तता को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक होने पर, उपरिलिखित विशेषज्ञ सदस्य के स्थान पर अथवा उसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों अथवा अपने क्षेत्राधीन किसी अन्य सार्वजनिक/निजी चिकित्सा संस्थान से किसी अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित करने का प्राधिकार है।

अधिकार क्षेत्र : बोर्ड को संपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार होगा।

बी. के. साहू बीमा आयुक्त

सं. आर-12/9/1/2007-हित-2--कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 14.12.1980 के संकल्प जिसमें महानिदेशक को ऐसी शिक्तयों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया है, के साथ पिठत क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 75 के अंतर्गत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 54 तथा 54-क के प्रयोजनार्थ तथा निगम के दिनांक 28.02.1976 के संकल्प (यथा संशोधित) के पैरा 4 के अंतर्गत मामलों की जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित चिकित्सा बोर्ड का गठन किया है:--

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. मॉडल अस्पताल, कोलम

अध्यक्ष

2. विशेषज्ञ (हड्डी) क.रा.बी. मॉडल अस्पताल, कोलम

सदस्य

3. विशेषज्ञ (शल्य चिकित्सा) क.रा.बी. मॉडल अस्पताल, कोलम

सदस्य

बोर्ड के अध्यक्ष को, जांच किए जाने वाले बीमाकृत व्यक्ति की निशक्ताता को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक होने पर, उपरिलिखित विशेषज्ञ सदस्य के स्थान पर अथवा उसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों अथवा अपने क्षेत्राधीन किसी अन्य सार्वजनिक/निजी चिकित्सा संस्थान से किसी अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित करने का प्राधिकार है।

अधिकार क्षेत्र: बोर्ड को संपूर्ण उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोलम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर क्षेत्राधिकार होगा।

बी. के. साहू बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2011

दिनांक 02.11.2007 की अधिसूचना के क्रम में निगम की 03.09.2010 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा परिवहन विनियम-2006 में निम्नानुसार पैरा 4(ग), (घ) व (ङ) समाविष्ट किए गए हैं।

4-ग. ग्रुप 'ग' व 'घ' कर्मचारियों के संबंध में आवास प्रभार की प्रतिपूर्ति तथा दौरे पर देय महंगाई भत्ता

आहरित ग्रेड वेतन	प्रतिदिन स्वीकार्य आवास प्रभार	प्रतिदिन स्वीकार्य महंगाई भत्ता
4,200/- रु. से 4,600/- रु. तक ग्रेड वेतन आहरित करने वाले अधिकारी	प्रतिदिन 750/- रु. तक	200/- रु. प्रतिदिन
4,200/- रु. से कम ग्रेड वेतन आहरित करने वाले अधिकारी	450/- रु. प्रतिदिन	180/- रु. प्रतिदिन

- 4-घ निम्नलिखित निर्णयों को यथा अनुमोदित समाविष्ट किया गया है:--
- 1. सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सभी शहरों के लिए दैनिक भत्ते की समान दरें स्वीकार्य होंगी।
- 2. परिशोधित वेतन ढॉचे पर देय महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाने पर सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए दौरे पर महंगाई भत्ता स्वत: 25% तक बढ़ जाएगा।
- 3. चूंकि होटल आवास कमरे के किराए की दर समय-समय पर परिशोधित हो जाती है इसलिए ऐसा प्रस्ताव है कि जब कभी उर्ध्वमुखी परिशोधन अपेक्षित हो तो महानिदेशक को क.रा.बी. निगम के अध्यक्ष के अनुमोदन से परिशोधित दरें कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा तदुपरान्त इसे निगम को रिपोर्ट किया जाए।
- 4-ङ पैरा को सड़क यात्रा के लिए मील भत्ता (पैरा 3घ) पर भारत सरकार के अनुदेश संख्या 19030/3/2008 स्वाः 4 दिनांक 23.09.2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

टी.के. भट्टाचार्य अपर आयुक्त (का. एवं. प्रशा.)

अहमदाबाद-380014, दिनांक 01 फरवरी 2011

सं. यू-16/53/2003/मैडी.11/(गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शिक्तयां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पीटी-फाइल-यू-13/12/13/2005-पीटीएमआर पीडी. 1) दिनांक 04.08.2008 द्वारा ये शिक्तयां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (रों) को मानकों के

अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी कने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. प्रहलाद भाई जीवनभाई श्रीमाली	20.02.2011 से 19.02.2012	कलोल (एन.जी.)

हरेन्द्र सिंह राज्य चिकित्सा आयुक्त

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ऑरोविल प्रतिष्ठान तमिलनाडु ऑरोविल... जनवरी, 2011

ऑरोविल प्रतिष्ठान स्थायी आदेश

- 1. सं. एम.एफ./1/2011/विनियम, जबिक ऑरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम 1988 की धारा 11(3) द्वारा ऑरोविल प्रतिष्ठान के मामलों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन की जिम्मेदारी तथा सभी शिक्तयों का प्रयोग और सभी कार्यों का निपटान, जिनका इस्तेमाल अथवा निपटान प्रतिष्ठान द्वारा किया जा सकता है, ऑरोविल प्रतिष्ठान के शासी बोर्ड में विहित है।
- 2. अब, इसलिए, शासी बोर्ड निर्णय लेता है कि स्थायी आदेश, जो उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, और भारतीय संसद और/अथवा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथोपरोक्त धारा 11(3) के प्रावधानों द्वारा कवर सभी मामले और ऐसे अन्य मामले, जिन्हें शासी बोर्ड उपयुक्त और आवश्यक समझे, ऑरोविल प्रतिष्ठान द्वारा समय-समय पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अधिसूचित किए जाएंगे :--
 - (क) यथोपरोक्त धारा 32 (2) (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में कोई स्थायी आदेश जारी नहीं किया जाएगा:
 - (ख) स्थायी आदेश, उन्हें अधिसूचित किए जाने से पहले अध्यक्ष द्वारा लिखित में अनुमोदित किए जाएंगे;
 - (ग) प्रतिष्ठान का सचिव अपने हस्ताक्षर और सील के तहत स्थायी आदेश अधिसूचित करेगा;
 - (घ) प्रतिष्ठान का सचिव अधिसूचित स्थायी आदेश को शासी बोर्ड के समक्ष और उसकी अगली बैठक में पृष्ठाकंन किए जाने हेतु प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा:
 - (ङ) प्रतिष्ठान का सिचव, स्थायी आदेश की प्रतियां उसके अधिसूचित किए जाने के बाद, केन्द्रीय सरकार को (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग) और ऐसे अन्य प्राधिकारियों और व्यक्तियों को भेजने की व्यवस्था करेगा जैसाकि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए;
 - (च) फाउंडेशन का सिचव, पहले जारी स्थायी आदेशों की क्रम संख्या के अनुसार व्यवस्था करेगा और इस प्रयोजनार्थ, पहले जारी स्थायी आदेशों की तद्नुसार पुन: संख्या डालेगा;

- आवश्यक और उपयुक्त समझे जाने पर अध्यक्ष/शासी निकाय स्थायी आदेश को संशोधित अथवा रद्द कर (छ) सकता है और संशोधित अथवा रद्द स्थायी आदेश के संबंध में, प्रतिष्ठान का सचिव ऊपर पैराग्राफ 4(क) से 4 (ङ) में वर्णित चरणों का पालन करेगा; और
- प्रतिष्ठान का सचिव, जारी सभी स्थायी आदेशों की एक गार्ड फाइल रखने की व्यवस्था करेगा और उसे, निदेश (ज) देने पर, शासी बोर्ड के सदस्यों को उपलब्ध कराएगा।
- 3. यह विनियम, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

एम. रामास्वामी सचिव

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय मौजुदा संविधि में योग/संशोधन

शीर्षक

1. मौजूदा संविधि 15(1) में संशोधन अध्ययन केन्द्रों तथा विभागों पर संविधि क्रमांक 15 मौजूदा रूप

- 15. (1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन केन्द्र
 - (1) गणित, सांख्यिकी तथा परिकलन (कम्प्यूटेशनल)
- होगें, यथा:--
 - विज्ञान केन्द्र
 - 2. मौजूदा संविधि 15(6)(अ) में योग अध्ययन केन्द्रों तथा विभागों पर संविधि क्रमांक 15

मौजूदा रूप

- 15.(6)(ए). विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग होंगे, यथा :--
 - (1) गणित विभाग
 - सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावित रूप

- विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन केन्द्र 15. (1) होगें, यथा:--
 - गणित, सांख्यिकी तथा परिकलन (1) (कम्प्युटेशनल) विज्ञान केन्द्र
 - मानविकी तथा भाषाएं केन्द्र (2)
 - सामाजिक विज्ञान केन्द्र (3)
 - वाणिज्य तथा प्रबंधन केन्द्र (4)
 - रसायन विज्ञान तथा औषधि (फार्मेसी) केन्द्र (5)
 - अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (6)

प्रस्तावित रूप

- विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग होंगे, 15. (1) यथा :--
 - गणित विभाग (1)
 - सांख्यिकी विभाग (2)
 - अंग्रेजी विभाग (3)
 - अर्थशास्त्र विभाग (4)
 - व्यापार प्रबंधन विभाग (5)

- (6) रसायन विज्ञान विभाग
- (7) संगणक (कम्प्यूटर) विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग
- (8) परिकलन (कम्प्यूटेशनल) विज्ञान विभाग प्रस्तावित रूप

शीर्षक

1. मौजूदा संविधि के शीर्षक में संशोधन

मौजूदा रूप

विश्वविद्यालय की संविधि

- 2. मौजूदा संविधि 15(1) में संशोधन अध्ययन केन्द्रों तथा विभागों पर संविधि क्रमांक 15 मौजूदा रूप
- 15. (1) विश्वविद्यालय में ऐसे अध्ययन केन्द्र होंगे जैसा संविधि में निर्दिष्ट है
- मौजूदा संविधि 15(6)(अ) में योग
 अध्ययन केन्द्रों तथा विभागों पर संविधि क्रमांक 15
 15.(6)(अ). विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग होगें,
 यथा :--
 - (1) गणित विभाग
 - (2) सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावित रूप

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधि

प्रस्तावित रूप

- 15. (1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन केन्द्र होगें, यथा :--
 - (1) गणित, सांख्यिकी तथा परिकलन(कम्प्यूटेशनल) विज्ञान केन्द्र

हरी सिंह सहायक पंजीयक

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 31st January 2011

No. R-12/19/1/2001-Bft. II—In exercise of the powers under Regulation 75 of the ESI (General) Regulation, 1950 read with the Resolution of the ESI Corporation dated 14.12.1980 empowering the Director General to exercise such powers, the Director General, Employees' State Insurance Corporation has constituted following Medical Board for the purpose of Section 54 and 54-A of ESI Act, 1948 and to examine and recommend the cases under Para 4 of the Corporation Resolution dated 28.02.76 (as amended):—

1. M. S. ESI Hospital, Gurgaon (Haryana)

Chairman

2. Specialist (Orthopaedics) ESI Hospital, Gurgaon

Member

3. Specialist (Surgery) ESI Hospital Gurgaon

Member

The Chairman of the Board is authorized to Co-opt any other specialist, if necessary, as member of the Board in lieu of or in addition to the 'Specialist member' mentioned above, keeping in view the disability of the Insured Person to be examined from State run Government Hospitals in constitution with the State Government concerned or from any other Public/Private Medical Institute(s) within his/her area of jurisdiction.

Jurisdiction: The Board will have the jurisdiction over areas falling under the Sub-Regional Office, Gurgaon.

B. K. SAHU Insurance Commissioner

No. R-12/19/1/2001-Bft. II—In exercise of the powers under Regulation 75 of the ESI (General) Regulation, 1950 read with the Resolution of the ESI Corporation dated 14.12.1980 empowering the Director General to exercise such powers, the Director General, Employees' State Insurance Corporation has constituted following Medical Board for the purpose of Section 54 and 54-A of ESI Act, 1948 and to examine and recommend the cases under Para 4 of the Corporation Resolution dated 28.02.76 (as amended):—

1. Medical Superintendent,

Chairman

ESI Model Hospital, Bapunagar (Gujarat)

2. Specialist (Orthopaedics), ESIMH, Bapunagar (Gujarat)

Member

3. Medical Officer (Surgical), ESIMH Bapunagar (Gujarat)

Member

The Chairman of the Board is authorized to Co-opt any other specialist, if necessary, as member of the Board in lieu of or in addition to the 'Specialist member' mentioned above, keeping in view the disability of the Insured Person to be examined from State run Government Hospitals in constitution with the State Government concerned or from any other Public/ Private Medical Institute(s) within his/her area of jurisdiction.

Jurisdiction: The Board will have the jurisdiction over areas falling under the Regional Office, Ahmedabad.

B. K. SAHU

Insurance Commissioner

No. R-12/19/1/2001-Bft. II—In exercise of the powers under Regulation 75 of the ESI (General) Regulation, 1950 read with the Resolution of the ESI Corporation dated 14.12.1980 empowering the Director General to exercise such powers, the Director General, Employees' State Insurance Corporation has constituted following Medical Board for the purpose of Section 54 and 54-A of ESI Act, 1948 to examine and recommend the cases under Para 4 of the Corporation Resolution dated 25.02.76 (as amended):—

 Medical Superintendent, ESI Model Hospital, Kollam Chairman

2. Specialist (Orthopaedics), ESIM Hospital, Kollam

Member

3. Specialist (Surgical), ESI Model Hospital, Kollam

Member

The Chairman of the Board is authorized to Co-opt any other specialist, if necessary, as member of the Board in lieu of or in addition to the 'Specialist member' mentioned above, keeping in view the disability of the Insured Person to be

examined from State run Government Hospitals in constitution with the State Government concerned or from any other Public/Private Medical Institute(s) within his/her area of jurisdiction.

Jurisdiction: The Board will have the jurisdiction over areas falling under the Sub-Regional Office, Kollam.

B. K. SAHU Insurance Commissioner

New Delhi, the 10th February 2011

In continuation of Notification dated 02.11.2007, Para 4 (C), (D) & (E) has been incorporated as below in TA/DA & Transport Regulation-2006 as per decision taken by the Corporation in its meeting held on 03.09.10.

4-C. Reimbursement of Lodging Charges in Respect of Group 'C' and 'D' Employees and DA Payable while on Tour :-

Grade Pay drawn	Lodging charges admissible per day	DA admissible per day
Officers drawing Grade Pay of Rs. 4200/- to Rs. 4,600/-	Upto Rs. 750/- per day	Rs. 200/- per day
Officers drawing Grade Pay of below of Rs. 4200/-	Upto Rs. 450/- per day	Rs. 180/- per day

- 4-D. Following decisions are incorporated as approved:
 - 1. For all categories of officers/employees uniform rates of DA will be applicable for all cities.
 - 2. For all categories of employees, Dearness Allowance on tour shall antomatically increased by 25%, wherein DA payable on the revised pay structure goes up by 50%.
 - 3. Since, the room rent of hotel accommodation rates get revised from time to time, it is proposed that whenever an upward revision is required, Director General may be authorized to implement the revised rates with the approval of Chairman of ESIC and the same may be reported to the Corporation subsequently.
- 4-E. The Para has been replaced with the Govt. of India instructions No. 19030/3/2008-E-IV dated 23.09.08 on Mileage Allowance for journey by Road (Para 3D).

T. K. BHATTACHARYA Additional Commissioner (P&A)

Ahmedabad, the 1st February 2011

No. U-16/53/2003/Med. II/(Guj.)—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on File No. Pt. File U-13/12/13/2005-PTMR (Med. I) dated 04.08.2008. I hereby authorize the following Doctors(s) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt:—

Name	Period	Name of Centre/Place/Distt./State
Dr. P. J. Shrimali	20.2.2011 to 19.2.2012	Kalol

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

AUROVILLE FOUNDATION, TAMIL NADU

Auroville, the

January 2011

THE AUROVILLE FOUNDATION STANDING ORDERS

No. AF/1/2011/Regulations—Whereas Section 11 (3) of the Auroville Foundation Act, 1988, vests the Auroville Foundation's Governing Board with the responsibility for the general superintendence, direction and management of the affairs of Auroville Foundation and to exercise all the powers and discharge all the functions which may be exercised or discharged by the Foundation.

- 2. Now, therefore, the Governing Board decides that "Standing Orders", not inconsistent with the provisions of the Act, ibid, and the Rules made thereunder, and without prejudice to the generality of the laws enacted by Parliament of India and/or the Legislatures of the States and the Union Territories, on all the matters covered by the provisions of Section 11 (3), ibid and also such other matters that the Governing Board may consider appropriate and necessary, shall be notified, from time to time, by the Auroville Foundation subject to the following conditions:—
 - (a) No Standing Order shall be issued on any of the matters specified in Section 32(2) (a) to (g), ibid;
 - (b) Chairman shall approve in writing the Standing Order before it is notified;
 - (c) Secretary to the Foundation shall notify the Standing Order under his hand and seal;
 - (d) Secretary to the Foundation shall arrange to place the notified Standing Order before the Governing Board at its subsequent meeting for endorsement;
 - (e) Secretary to the Foundation shall arrange to send copies of the Standing Order, after its notification, to the Central Government (Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education) and to such other authorities and individuals as may be decided by the Chairman from time to time;
 - (f) Secretary to the Foundation shall arrange to chronologically number the Standing Orders issued earlier and, for this purpose, shall accordingly renumber the Standing Orders already issued;
 - (g) Chairman/Governing Board may amend or revoke a Standing Order as and when considered necessary and appropriate, and, in respect of the amended or revoked Standing Order, Secretary to the Foundation shall follow the steps mentioned at paragraph 4 (a) to 4 (e) supra; and
 - (h) Secretary to the Foundation shall arrange to maintain a Guard File of all Standing Orders issued and make it available to the members of the Governing Board as and when directed to do so.
- 3. This regulation shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

M. RAMASWAMY

Secy.

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN

AMENDMENT AND ADDITION TO THE EXISTING STATUTES

Title

1. Amendment in the existing Statute 15 (1)

Statute 15 on the Schools of Studies and Departments

As existing

As proposed

15. (1) The University shall have the following Schools of Studies, namely:—

15. (1) The University shall have the following Schools of Studies, namely:—

- (i) School of Mathematics, Statistics and Computational Sciences
- (i) School of Mathematics, Statistics and Computational Sciences
- (ii) School of Humanities and Languages
- (iii) School of Social Science
- (iv) School of Commerce and Management
- (v) School of Chemical Sciences and Pharmacy
- (vi) School of Engineering and Technology
- Addition to the existing Statute 15(6)(a)
 Statute 15 on the Schools of Studies and Departments
 As existing
- 15 (1) The University shall have the following Departments, namely:—
 - (i) Department of Mathematics
 - (ii) Department of Statistics

As proposed

- 15. (1) The University shall have the following Departments, namely:—
 - (i) Department of Mathematics
 - (ii) Department of Statistics
 - (iii) Department of English
 - (iv) Department of Economics
 - (v) Department of Business Management
 - (vi) Department of Chemistry
 - (vii) Department of Computer Science & Engineering
 - (viii) Department of Computational Sciences

Title

1. Amendment in the existing title of the Statute

As existing

The Statutes of the University

2. Amendment in the existing Statute 15(1)

Statute 15 on the Schools of Studies and Departments

As existing

15. (1) The University shall have such Schools of Studies as may be specified in the Statutes.

As proposed

The Statues of the Central University of Rajasthan

- As proposed
 - 15. (1) The University shall have the following Schools of Studies, namely:—
 - (i) School of Mathematics, Statistics and Computational Sciences.
- 3. Addition of Statutes 15(6) (a) to the existing Statute 15 Statute 15 on the Schools of Studies and Departments
- 15 (6) (a) The University shall have the following Departments, namely:--
 - (i) Department of Mathematics
 - (ii) Department of Statistics

HARI SINGH Asstt. Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011